Test Cloud

Daily करेंट अफेयर्स

09 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. नीति आयोग ने NER जिला SDG सूचकांक 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया और मिजोरम का हनाहथियाल जिला रैंकिंग में शीर्ष पर रहा।

जुलाई 2025 में, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER) जिला सतत विकास सूचकांक (SDG) रिपोर्ट 2023-24 का दूसरा संस्करण जारी किया, जिसमें पूर्वोत्तर के जिलों की सतत विकास लक्ष्य (SDG) प्रगति का मूल्यांकन किया गया। मिज़ोरम का हनाहथियाल ज़िला शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा, जिसने भारत के 2030 के एजेंडे के अनुरूप सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में क्षेत्रीय प्रयासों को उजागर किया।

• सूचकांक रिपोर्ट का विमोचन नीति आयोग की उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के CEO बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) के सचिव चंचल कुमार और भारत में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की स्थानीय प्रतिनिधि डॉ. एंजेला लुसिगी ने किया। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम निदेशक (SDGs) राजीब कुमार सेन के साथ-साथ नीति आयोग और MoDoNER के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

• यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDoNER) के सहयोग से और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) की तकनीकी सहायता से विकसित किया गया है।

• यह भारत के 17 सतत विकास लक्ष्यों के प्रति जिला-स्तरीय प्रदर्शन को मापता है और पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करता है।

Key Points:-

(i) सूचकांक के 2023-24 संस्करण में पूर्वोत्तर क्षेत्र के 131 जिलों में से 121 (92%) का मूल्यांकन किया गया, जो पिछले संस्करण के 103 जिलों से बढ़कर है। इस मूल्यांकन में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) से जुड़े 84 संकेतकों का उपयोग किया गया है और जिलों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: अचीवर (100), फ्रंट-रनर (65-99), परफॉर्मर (50-64), और एस्पिरेंट (<50)।

(ii) रिपोर्ट के अनुसार, 103 जिलों को "अग्रणी" श्रेणी में रखा गया है, जबकि 18 जिले "प्रदर्शनकारी" श्रेणी में आते हैं। किसी भी जिले को "अचीवर" श्रेणी में स्थान नहीं मिला। इस वर्गीकरण से राज्यों को प्रगति पर नज़र रखने और विकास प्रयासों को उन जगहों पर केंद्रित करने में मदद मिलती है जहाँ इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

(iii) मिज़ोरम का हनाहथियाल ज़िला 81.43 अंकों के साथ सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा, उसके बाद मिज़ोरम का चम्फाई ज़िला 79.86 अंकों के साथ दूसरे और त्रिपुरा का गोमती ज़िला 78.79 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। इसके विपरीत, अरुणाचल प्रदेश का अंजॉ ज़िला 58.71 अंकों के साथ सबसे निचले स्थान पर रहा, जिससे वह "प्रदर्शनकारी" श्रेणी में आ गया। यह ज़िलों के बीच विकास में असमानता और लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता को दर्शाता है।

2. पंजाब ने प्रति परिवार ₹10 लाख वार्षिक स्वास्थ्य कवर के साथ 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की।

8 जुलाई, 2025 को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ चंडीगढ़ में राज्यव्यापी 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' शुरू की।

• इस पहल का उद्देश्य पंजाब के प्रत्येक स्थायी निवासी परिवार को, चाहे उनकी आय, आयु या व्यवसाय कुछ भी हो, 10 लाख रुपये का व्यापक वार्षिक कैशलेस और पेपरलेस चिकित्सा कवरेज प्रदान करना है।

• इस ऐतिहासिक योजना से लगभग 65 लाख परिवारों (लगभग 3 करोड़ व्यक्ति) को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिनमें सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी, किसान, मजदूर और व्यवसाय मालिक शामिल हैं।

• सरकार 2 अक्टूबर, 2025 से आधार या वोटर ID से जुड़े डिजिटल 'सेहत कार्ड' जारी करेगी, जिससे सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।

Key Points:-

(i) केंद्रीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से नामांकित लाभार्थियों को ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा, जिससे उनकी कुल कवरेज बढ़कर ₹10 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। यह राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों को जोड़कर समानता सुनिश्चित करता है। केंद्रीय आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में पहले से नामांकित लाभार्थियों को ₹5 लाख का अतिरिक्त टॉप-अप कवर मिलेगा, जिससे उनकी कुल कवरेज बढ़कर ₹10 लाख प्रति वर्ष हो जाएगी। यह राज्य और केंद्रीय स्वास्थ्य देखभाल प्रावधानों को जोड़कर समानता सुनिश्चित करता है।

(ii) इस नीति के क्रियान्वयन और संचालन हेतु 2025-26 के राज्य बजट में ₹778 करोड़ आवंटित किए जाने का अनुमान है। इसे पंजाब में अब तक की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल माना जा रहा है, जो ₹5 लाख वाली आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री सरबत सेहत बीमा योजना जैसी पिछली योजनाओं से भी आगे निकल गई है।

(iii) जटिल दस्तावेज़ीकरण और पात्रता प्रतिबंधों को समाप्त करके, इस योजना का उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करना, जेब से होने वाले चिकित्सा व्यय को काफी कम करना और सभी निवासियों, विशेष रूप से वंचित और ग्रामीण समुदायों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक समान पहुंच सुनिश्चित करना है।

3. स्टार्टअप पॉलिसी फोरम ने भारत के डीप-टेक परिदृश्य को उन्नत करने के लिए '#100DesiDeepTechs' लॉन्च किया।

स्टार्टअप पॉलिसी फोरम (SPF) ने #100DesiDeepTechs लॉन्च किया है, जो अपनी तरह की पहली बहु-हितधारक पहल है और भारत के शीर्ष 100 डीप-टेक स्टार्टअप्स की पहचान और उन्हें सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्टार्टअप इंडिया (DPIIT), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) स्टार्टअप हब और IIT-मद्रास द्वारा समर्थित इस पहल का उद्देश्य नीतिगत संवाद को गति देना और डीप टेक्नोलॉजी में वैश्विक नेतृत्व की ओर भारत की यात्रा को तेज़ करना है।

- **#100DesiDeepTechs सेमीकंडक्टर, रक्षा प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, ड्रोन, इलेक्ट्रिक वाहन, जैव प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, उन्नत विनिर्माण और संचार अवसंरचना जैसी विविध श्रेणियों में स्टार्टअप्स से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 है।**

- **चयनित स्टार्टअप प्रमुख हितधारकों—नीति निर्माताओं, निवेशकों, उद्योग विशेषज्ञों, क्षेत्र नियामकों और शैक्षणिक संस्थानों—के साथ विशेष, बंद कमरे में डीपटेक संवाद में भाग लेंगे ताकि बाधाओं का निदान किया जा सके और समाधान तैयार किए जा सकें। इन संवादों से प्राप्त अंतर्दृष्टि सीधे एक व्यापक नीति श्वेतपत्र में शामिल की जाएगी।**

- **इस श्वेतपत्र का अनावरण "डीपटेक बैठक" नामक एक उच्च-स्तरीय कार्यक्रम में किया जाएगा, जहाँ चुनिंदा संस्थापक, नियामक, निवेशक और सरकारी अधिकारी एकत्रित होंगे। यह पहल एसपीएफ के डीपटेक नीति अनुसंधान केंद्र (CDPR) की नींव भी रखेगी ताकि निरंतर जुड़ाव बना रहे और इस क्षेत्र के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया जा सके।**

Key Points:-

(i) चयनित स्टार्टअप्स को समर्थन देने के लिए, अनुभवी संस्थापकों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और गहन तकनीक विशेषज्ञों से बना एक मेंटर बोर्ड रणनीतिक मार्गदर्शन, महत्वपूर्ण नेटवर्क तक पहुंच और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

(ii) चयन प्रक्रिया IIT-मद्रास द्वारा संचालित की जाएगी, जिसका श्वेतपत्र SPF के ज्ञान साझेदार इकिगाई लॉ द्वारा तैयार किया जाएगा और कार्यक्रम का प्रबंधन नीति सलाहकार काइओ द्वारा किया जाएगा।

(iii) यह पहल राष्ट्रीय नीतिगत प्राथमिकताओं के अनुरूप है, जैसे कि ₹1 लाख करोड़ की अनुसंधान, विकास एवं नवाचार (RDI) योजना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समर्पित डीपटेक फंड ऑफ फंड्स। SPF पहल ऐसे समय में शुरू हुई है जब सरकार ने भारत के डीप-टेक पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिए फंड ऑफ फंड्स के तहत अतिरिक्त ₹10,000 करोड़ आवंटित किए हैं।

4. बिहार कैबिनेट ने सरकारी नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों तक महिलाओं के लिए 35% आरक्षण सीमित कर दिया।

8 जुलाई, 2025 को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली बिहार सरकार ने एक नीतिगत बदलाव को मंजूरी दी, जिसके तहत राज्य सरकार की नौकरियों में

महिलाओं के लिए मौजूदा 35% आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित कर दिया गया, तथा अन्य राज्यों की महिला आवेदकों को इसमें शामिल नहीं किया गया।

• इससे पहले, 2016 में शुरू किए गए इस कोटे के लिए पूरे भारत की महिलाएं पात्र थीं, लेकिन नए अधिवास नियम के तहत केवल स्थायी निवासियों को ही इसका लाभ मिलेगा—जो कम से कम तीन साल से यहाँ रह रही हों, संपत्ति की मालिक हों, या किसी स्थानीय व्यक्ति से विवाहित हों। हालाँकि, इस कोटे के तहत पहले से ही सेवारत अनिवासी महिलाओं की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

Key Points:-

(i) मंत्रिमंडल ने 'संबल' योजना के तहत सहायता उपायों की भी घोषणा की, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को 50,000 रुपये और UPSC मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

(ii) इसके अतिरिक्त, राज्य ने 24 सदस्यीय बिहार युवा आयोग का गठन किया, जिसमें एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और 45 वर्ष से कम आयु के सात सदस्य शामिल होंगे। आयोग का कार्य बिहार के भीतर और प्रवासी समुदायों के बीच शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास और युवा कल्याण के लिए नीतियों की सिफारिश करना है।

(iii) ये कदम आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से पहले उठाए गए हैं, जो नीतीश कुमार सरकार द्वारा अपने "जाति-तटस्थ" मतदाता आधार में महिला मतदाताओं को शामिल करने के रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है। अधिवास-आधारित आरक्षण स्थानीय रोज़गार संरक्षण पर बढ़ते राजनीतिक ज़ोर को दर्शाता है।

5. भारत सरकार ने अनुकरणीय हरित प्रथाओं के लिए तीन खदानों को सात सितारा रेटिंग प्रदान की।

जुलाई 2025 में, भारत सरकार ने खान मंत्रालय के माध्यम से, टिकाऊ खनन में उनके असाधारण प्रदर्शन को मान्यता देते हुए, तीन खदानों को पहली बार प्रतिष्ठित सेवन-स्टार रेटिंग प्रदान की। ये पुरस्कार जयपुर में आयोजित एक समारोह में प्रदान किए गए, जिसमें केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुए।

• सम्मानित खदानें थीं नाओकारी चूना पत्थर खदान (अल्ट्राटेक सीमेंट) - यह सम्मान पाने वाली भारत की पहली चूना पत्थर खदान - नोआमुंडी लौह अयस्क खदान (टाटा स्टील) और कम्माथारू खदान (सैंडूर मैंगनीज एंड आयरन ओर लिमिटेड), जिनमें से सभी ने लगातार पांच वर्षों तक पांच सितारा रेटिंग बनाए रखी थी, तथा दो चरणों के कड़े मूल्यांकन को पारित किया था।

Key Points:-

(i) स्टार रेटिंग ऑफ़ माइन्स कार्यक्रम के तहत सात-सितारा रैंकिंग सर्वोच्च है, जो चार स्थिरता स्तंभों: प्रभाव प्रबंधन, प्रगतिशील खदान बंद करना और पुनर्स्थापन, सामाजिक कल्याण और पारदर्शी रिपोर्टिंग के आधार पर प्रदर्शन का आकलन करती है। योग्यता प्राप्त करने के लिए, खदान को इन

मॉड्यूल में कम से कम 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे और फिर भारतीय खान ब्यूरो (IBM) द्वारा स्व-मूल्यांकन और उसके बाद क्षेत्रीय सत्यापन पास करना होगा।

(ii) विशिष्ट सात-सितारा विजेताओं के अलावा, इस समारोह में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल 98 खदानों को मान्यता दी गई, जिनमें से 95 को पाँच-सितारा रेटिंग मिली, जो देश भर में स्थायी सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने में हो रही वृद्धि को दर्शाती है। 2014-15 में शुरू की गई इन रेटिंग्स का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक विकास को बढ़ावा देना है।

6. आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को वैश्विक क्वांटम हब के रूप में स्थापित करने के लिए अमरावती क्वांटम वैली घोषणा को मंजूरी दी।

7 जुलाई, 2025 को, आंध्र प्रदेश सरकार ने अमरावती क्वांटम वैली घोषणापत्र को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी, जिससे अमरावती में क्वांटम प्रौद्योगिकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढाँचा स्थापित होगा। इस घोषणापत्र का उद्देश्य राज्य को एक अग्रणी क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र में बदलना है, जिसका लक्ष्य 1 जनवरी, 2029 तक 1 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करना है।

• यह घोषणापत्र 30 जून, 2025 को विजयवाड़ा में आयोजित क्वांटम वैली कार्यशाला का परिणाम है, जहाँ सरकारी अधिकारियों, उद्योग जगत के दिग्गजों, शैक्षणिक विशेषज्ञों और स्टार्टअप्स ने सहयोग किया था। इसमें क्वांटम अनुसंधान, प्रतिभा विकास, बुनियादी ढाँचे के निर्माण और वैश्विक साझेदारी जैसी साझा प्रतिबद्धताओं को रेखांकित किया गया है।

• एक प्रमुख पहल में 12 महीनों के भीतर भारत के सबसे बड़े ओपन क्वांटम टेस्टबेड, QChipIN की स्थापना शामिल है। यह 'लिविंग लैब' बुनियादी ढांचा क्वांटम कंप्यूटर, कुंजी वितरण (QKD) फाइबर लिंक और सेंसर प्लेटफॉर्म को स्वास्थ्य-तकनीक, वित्त, रक्षा, रसद और अंतरिक्ष क्षेत्रों में पायलट परियोजनाओं के साथ एकीकृत करेगा।

Key Points:-

(i) घोषणा के तहत, IBM का क्वांटम सिस्टम 2 जनवरी 2026 तक स्थापित होने की उम्मीद है, जिससे 100 क्वांटम एल्गोरिदम का परीक्षण संभव हो सकेगा। 2027 तक, तीन और क्वांटम सिस्टम—सुपरकंडक्टिंग सर्किट, ट्रैप्ड आयन और फोटोनिक क्यूबिट—स्थापित करने की योजना है। रोडमैप का लक्ष्य 2028 तक सालाना 1,000 एल्गोरिदम तक पहुँचना और 2029 तक 1,000 प्रभावी क्यूबिट तक पहुँचना है।

(ii) एक मजबूत घरेलू आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए, अमरावती क्वांटम वैली क्यूबिट प्लेटफॉर्म, क्रायो-इलेक्ट्रॉनिक्स, क्वांटम चिप्स, सिंगल-फोटॉन डिटेक्टर और फोटोनिक पैकेज का उत्पादन करेगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 5,000 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात करना है। शासन में एक बहु-हितधारक मिशन बोर्ड, एक वैश्विक क्वांटम सहयोग परिषद और 2026 से शुरू होने वाला एक वार्षिक विश्व क्वांटम एक्सपो शामिल होगा।

7. AP ने छह शहरों में मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए AI-आधारित SMoSS पहल शुरू की।

जुलाई 2025 में, आंध्र प्रदेश सरकार ने स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम (SMoSS) लॉन्च किया, जिससे यह डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों से निपटने के लिए AI-एकीकृत निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। यह परियोजना मच्छरों पर सक्रिय नियंत्रण के लिए रीयल-टाइम डेटा प्रदान करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) उपकरणों के संयोजन का उपयोग करती है।

- **SMoSS पहल आंध्र प्रदेश के नगर प्रशासन और शहरी विकास (MA&UD) विभाग द्वारा छह नगर निगमों में 66 स्थानों पर कार्यान्वित की जा रही है।**
- **इनमें ग्रेटर विशाखापत्तनम (16 स्थान), विजयवाड़ा (28), नेल्लोर (7), कुरनूल (6), राजमहेंद्रवरम (5) और काकीनाडा (4) जैसे प्रमुख शहरी क्षेत्र शामिल हैं, जो इसे देश में सबसे बड़ी मच्छर निगरानी पहलों में से एक बनाता है।**
- **इस परियोजना का उद्देश्य मच्छरों की आबादी पर प्रभावी निगरानी और उसे कम करने के लिए एआई-संचालित स्मार्ट मच्छर सेंसर, हीट मैप, स्वचालित जाल और ड्रोन-आधारित लार्विसाइड छिड़काव का उपयोग करना है। निगरानी डेटा को एक केंद्रीय नियंत्रण प्रणाली तक पहुँचाने और उसे IoT से जुड़े उपकरणों से प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा।**

Key Points:-

(i) यह प्रणाली मच्छरों की विभिन्न विशेषताओं, जैसे प्रजातियाँ, घनत्व और लिंग, के साथ-साथ तापमान और आर्द्रता जैसी स्थानीय पर्यावरणीय स्थितियों पर नज़र रखेगी। संभावित प्रकोपों का पूर्वानुमान लगाने और शीघ्र हस्तक्षेप शुरू करने के लिए इस जानकारी का निरंतर विश्लेषण किया जाएगा।

(ii) एकत्रित सभी डेटा को एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड में एकीकृत किया जाएगा, जो नगरपालिका अधिकारियों और स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए सुलभ होगा। इससे डेटा-आधारित निर्णय लेने में मदद मिलेगी, जिससे अधिकारी विशिष्ट स्थानों पर मच्छरों की बढ़ती संख्या या बीमारी के खतरे की स्थिति में तुरंत कार्रवाई कर सकेंगे।

(iii) SMoSS मॉडल राज्य की व्यापक स्मार्ट स्वास्थ्य अवसंरचना रणनीति के अनुरूप है और AI-एकीकृत सार्वजनिक सेवाओं के लिए भारत के दृष्टिकोण का समर्थन करता है। उन्नत तकनीकों को अपनाकर, आंध्र प्रदेश का लक्ष्य अन्य भारतीय राज्यों के लिए एक मिसाल कायम करना और दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा में योगदान देना है।

INTERNATIONAL

1. प्रधानमंत्री मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान - ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया।

रियो डी जेनेरियो में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद ब्राज़ील की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, नेशनल ऑर्डर ऑफ़ द सदर्न क्रॉस के प्रतिष्ठित ग्रैंड कॉलर से सम्मानित किया गया।

• यह सम्मान राष्ट्रपति लुईज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने 8 जुलाई, 2025 को ब्रासीलिया के अल्वोराडा पैलेस में आयोजित एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया, जिसमें रणनीतिक भारत-ब्राज़ील साझेदारी को मज़बूत करने में मोदी के योगदान को मान्यता दी गई।

• यह सम्मान 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से प्रधानमंत्री मोदी को प्राप्त 26वाँ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो उनके बढ़ते वैश्विक कूटनीतिक प्रभाव और नेतृत्व क्षमता को रेखांकित करता है। यह सम्मान विशेष रूप से ब्राज़ील द्वारा भारत की कूटनीतिक पहलों और वैश्विक दक्षिण सहयोग में उसकी भूमिका के समर्थन के अनुरूप है।

• राष्ट्रपति भवन में भव्य माहौल में आयोजित इस समारोह में मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर और 114 घुड़सवारों की सलामी दी गई। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों—जिसमें बटाला मुंडो बैंड द्वारा सांबा-रेगे संगीत और भारतीय शास्त्रीय हारमोनियम वादन शामिल थे—ने भारत-ब्राजील सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गर्मजोशी को रेखांकित किया।

Key Points:-

(i) राष्ट्रपति लूला के साथ अपने संयुक्त प्रेस वक्तव्य में, प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा आभार व्यक्त किया और इस पुरस्कार को ब्राज़ीलियाई लोगों के भारत के प्रति अटूट स्नेह का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि यह पुरस्कार व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रौद्योगिकी और जलवायु सहयोग के क्षेत्र में भारत-ब्राज़ील संबंधों को निरंतर प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगा।

(ii) ब्राजील की मान्यता प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है: राष्ट्रपति लूला ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत के लिए ब्राजील के समर्थन की पुष्टि की, और दोनों नेताओं ने आतंकवाद पर शून्य-सहिष्णुता के रुख को रेखांकित किया, जबकि द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

(iii) यह सम्मान उच्च स्तरीय भारतीय राजनयिक मान्यताओं की एक श्रृंखला के अनुरूप है - मोदी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो, घाना, मॉरीशस और साइप्रस जैसे देशों से सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, जो वैश्विक दक्षिण साझेदारी में भारत की मजबूत भूमिका को दर्शाता है।

2. PM मोदी ने ऐतिहासिक 5-राष्ट्र वैश्विक दक्षिण यात्रा पूरी की: घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया में संबंधों को मजबूत किया।

2-9 जुलाई, 2025 के बीच, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया को कवर करते हुए 5 देशों का व्यापक राजनयिक दौरा किया - यह एक दशक में उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा थी और वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत किया।

• उन्होंने घाना से शुरुआत की (2-3 जुलाई)—लगभग 30 वर्षों में उनकी पहली यात्रा—घाना की संसद को संबोधित किया, 21 तोपों की सलामी ली और संस्कृति, स्वास्थ्य, मानकीकरण और संस्थागत संवाद के लिए चार समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। मोदी को राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामा द्वारा घाना के ऑर्डर ऑफ द स्टार के अधिकारी से भी सम्मानित किया गया।

• 3-4 जुलाई को, उन्होंने त्रिनिदाद और टोबैगो का दौरा किया, जो 1999 के बाद उनकी पहली आधिकारिक यात्रा थी। वहाँ उन्होंने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया और बुनियादी ढाँचे तथा फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में छह समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू ने उन्हें ऑर्डर ऑफ़ द रिपब्लिक ऑफ़ त्रिनिदाद और टोबैगो (ORTT) से सम्मानित किया।

• 4-5 जुलाई के बीच, मोदी ने अर्जेंटीना का दौरा किया, जो 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेवियर मिली से मुलाकात की और कृषि, व्यापार, ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिजों और तकनीक में अवसरों पर चर्चा की।

Key Points:-

(i) 5 से 7 जुलाई तक, उन्होंने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जिससे बहुपक्षीय मंचों पर भारत की स्थिति मजबूत हुई और बाद में द्विपक्षीय कार्यक्रमों के लिए ब्रासीलिया में राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से मुलाकात की, जिसमें ब्राजील के ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया जाना भी शामिल था।

(ii) नामीबिया में अपना दौरा (8-9 जुलाई) समाप्त करते हुए, मोदी 27 वर्षों में वहाँ जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उन्होंने संसद को संबोधित किया, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल तकनीक (UPI सहित) पर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए और नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ़ द मोस्ट एंशिएंट वेल्विट्शिया मिराबिलिस से सम्मानित हुए।

(iii) इस दौरे में कूटनीति, प्रवासी भारतीयों तक पहुंच, सांस्कृतिक जुड़ाव और रणनीतिक वार्ता का मिश्रण देखने को मिला, क्योंकि मोदी ने भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत किया और अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा, स्वास्थ्य और रक्षा पर सहयोग को बढ़ावा दिया।

ECONOMY & BUSINESS

1. एयरएशिया बरहाद ने 50 A321XLR जेट के लिए 12.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एयरबस सौदे पर हस्ताक्षर किए।

मलेशिया की राजधानी ए बरहाद की पूर्ण-सेवा सहायक कंपनी एयरएशिया बरहाद ने 50 A321XLR लंबी दूरी के संकीर्ण-बॉडी विमानों की खरीद के लिए 7 जुलाई, 2025 को पेरिस में एयरबस के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं।

- **12.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के इस समझौते में अतिरिक्त 20 जेट विमानों के रूपांतरण अधिकार शामिल हैं, जो इसकी वैश्विक विस्तार योजनाओं में एक रणनीतिक छलांग है।**

- **ये अगली पीढ़ी के A321XLR विमान 4,700 नॉटिकल मील तक की विस्तारित-रेंज कनेक्टिविटी प्रदान करेंगे, साथ ही मौजूदा A321neo मॉडल की तुलना में प्रति सीट 20% तक कम ईंधन खपत भी करेंगे। इनकी डिलीवरी 2028 से 2032 के बीच निर्धारित है, जो एयरएशिया के उस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के अनुरूप है जिसके तहत 2030 तक सालाना 15 करोड़ यात्रियों को ले जाने वाला पहला कम लागत वाला नैरो-बॉडी नेटवर्क वाहक बनना है।**

- **यह समझौता ऐसे समय में हुआ है जब एयरएशिया अपनी वित्तीय पुनर्गठन प्रक्रिया के पूरा होने के करीब है और मलेशिया के PN17 वित्तीय रूप से संकटग्रस्त वर्गीकरण से बाहर आ रही है।**

Key Points:-

(i) एयरबस के CEO क्रिश्चियन शेरेर और एयरएशिया के CEO टोनी फर्नांडीस ने मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम की उपस्थिति में पेरिस में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

(ii) यह कदम एयरएशिया की वैश्विक मल्टी-हब रणनीति को मजबूत करता है - जो कुआलालंपुर और बैंकॉक पर केंद्रित है - तथा मध्य एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप में नई लंबी दूरी की उड़ानें प्रदान करता है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. एप्पल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का नेतृत्व करने के लिए सबीह खान को नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया।

8 जुलाई, 2025 को, Apple ने सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी (COO) नियुक्त करने की घोषणा की, जो जेफ विलियम्स की जगह लेंगे, जो इस साल के अंत में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। यह बदलाव दुनिया की सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनी में एक सावधानीपूर्वक नियोजित नेतृत्व उत्तराधिकार को दर्शाता है।

- **सबीह खान, एक भारतीय-अमेरिकी, जिनका जन्म 1966 में मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश (भारत) में हुआ था, 1995 से एप्पल के साथ हैं। उन्होंने 2019 से परिचालन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है, और एप्पल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला, आपूर्तिकर्ता जिम्मेदारी कार्यक्रमों और उत्पाद**

वितरण प्रणालियों की देखरेख की है - जिससे वे अमेरिका और एशिया भर में प्रमुख विनिर्माण रणनीतियों के वास्तुकार बन गए हैं।

• खान की तकनीकी और प्रबंधकीय नींव में टफ्ट्स विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग और अर्थशास्त्र में दोहरी स्नातक डिग्री और रेनसेलर पॉलिटेक्निक संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातकोत्तर डिग्री शामिल है। एप्पल में शामिल होने से पहले, उन्होंने जीई प्लास्टिक्स में एप्लिकेशन डेवलपमेंट इंजीनियर और प्रमुख-खाता तकनीकी प्रमुख के रूप में काम किया।

Key Points:-

(i) एप्पल के CEO टिम कुक ने खान की सराहना करते हुए उन्हें एक "शानदार रणनीतिकार" और एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला के लचीलेपन का एक प्रमुख वास्तुकार बताया और कोविड-19 महामारी के दौरान उनके नेतृत्व और हरित विनिर्माण पहलों को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। कंपनी वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं और बदलते विनिर्माण बदलावों—जैसे कि एप्पल द्वारा अगले साल तक भारत में आईफोन का उत्पादन बढ़ाने के कदम—के बीच उनकी विशेषज्ञता को महत्वपूर्ण मानती है।

(ii) COO के रूप में, खान से एप्पल के वैश्विक संचालन और लॉजिस्टिक्स की ज़िम्मेदारी संभालने की उम्मीद है, जिससे अशांत व्यापार काल के दौरान एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता को मज़बूती मिलेगी। यह बदलाव एक महत्वपूर्ण मोड़ पर आया है: जेफ विलियम्स, जिन्होंने 2015 से एप्पल के संचालन का प्रबंधन किया था और एप्पल वॉच डिज़ाइन और स्वास्थ्य पहलों की प्रत्यक्ष देखरेख की थी, अपनी सेवानिवृत्ति तक सलाहकार के रूप में काम करते रहेंगे।

(iii) यह नियुक्ति खान को एप्पल में दूसरे सबसे बड़े कार्यकारी अधिकारी के रूप में स्थापित करती है और कंपनी की अनुभवी आंतरिक योजना पर बढ़ती निर्भरता को रेखांकित करती है। उनका उदय वैश्विक तकनीकी दिग्गजों को आकार देने वाले भारतीय मूल के नेतृत्व का एक सशक्त प्रमाण भी है।

2. BMW ग्रुप इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को अध्यक्ष एवं CEO नियुक्त किया।

8 जुलाई 2025 को, BMW ग्रुप इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को अपना नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने की घोषणा की, जो 1 सितंबर 2025 से प्रभावी होगा। बरार विक्रम पावाह का स्थान लेंगे, जो BMW ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नेतृत्व करेंगे, जो भारत में लक्जरी ऑटोमेकर के संचालन के भीतर एक रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तन को चिह्नित करेगा।

• बरार के पास भारतीय ऑटोमोटिव क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जिसमें किआ इंडिया, मारुति सुजुकी, वोक्सवैगन पैसेंजर कार्स, जनरल मोटर्स इंडिया, निसान मोटर इंडिया, ग्रेट वॉल मोटर आदि में वरिष्ठ नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल हैं।

• हाल ही में, किआ इंडिया में वरिष्ठ उपाध्यक्ष - बिक्री और विपणन के रूप में, उन्होंने कंपनी को 1 मिलियन इकाइयों की संचयी बिक्री के आंकड़े को पार कराया और कैरेंस, ईवी 6, सोरेंटो और फ्लैगशिप EV 9 सहित सफल लॉन्च का नेतृत्व किया।

Key Points:-

(i) बरार ने पंजाब के थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की है, और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के सीनियर एक्जीक्यूटिव लीडरशिप प्रोग्राम से स्नातक हैं - उनकी पृष्ठभूमि बिक्री, विपणन, आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक अनुभव में रणनीति बनाने की उनकी क्षमता को रेखांकित करती है।

(ii) नियुक्ति का स्वागत करते हुए, BMW समूह में एशिया-प्रशांत और संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जीन-फिलिप पैरेन ने इस बात पर जोर दिया कि "भारत BMW समूह के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में से एक है" और भारतीय ऑटोमोटिव परिदृश्य में बरार की गहरी अंतर्दृष्टि पर प्रकाश डाला, जो परिचालन को मजबूत करने और भारत में अगले विकास चरण को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।

(iii) हरदीप सिंह बरार के नेतृत्व में, BMW ग्रुप इंडिया - जो पहले से ही H12025 में 7,774 कारों और 2,569 मोटरसाइकिलों के साथ रिकॉर्ड बिक्री का दावा कर रहा है - अपने लक्जरी पोर्टफोलियो को बढ़ाने, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में तेजी लाने, डिजिटलीकरण को बढ़ाने और असाधारण ग्राहक अनुभव प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

SPORTS

1. एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025: चीन पदक तालिका में शीर्ष पर, भारत दूसरे स्थान पर।

बीजिंग में विकलांग व्यक्तियों के लिए चीन खेल प्रशासन केंद्र में 2-7 जुलाई, 2025 को आयोजित एशियाई पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में चीन ने 17 पदक (10 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य) के साथ दबदबा बनाया, जबकि भारत ने 9 पदक (3 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य) जीतकर सराहनीय दूसरा स्थान हासिल किया।

- **भारतीय दल में 28 एथलीट और 69 अधिकारी शामिल थे, जिन्होंने रिकर्व ओपन, कंपाउंड ओपन और डब्ल्यू1 (व्हीलचेयर) श्रेणियों में 14 स्पर्धाओं में भाग लिया। यह टूर्नामेंट अमेरिका के लॉस एंजिल्स में होने वाले 2028 ग्रीष्मकालीन पैरालिंपिक के लिए क्वालीफायर भी रहा।**

- **पैरालंपिक चैंपियन हरविंदर सिंह, रिकर्व में विश्व नंबर 1, ने दो स्वर्ण जीते - क्वालीफायर में 663 अंकों का प्रतियोगिता रिकॉर्ड बनाया और रिकर्व पुरुष ओपन सोलो और रिकर्व मिश्रित टीम (भावना के साथ जोड़ी) फाइनल में हावी रहे।**

Key Points:-

(i) शीतल देवी और ज्योति की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने भी चीन को 148-143 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह जीत चीन के अंतिम क्षणों में लड़खड़ाने के बाद मिली, जिससे कड़े दबाव वाले फाइनल में भारत की दृढ़ता का पता चलता है।

(ii) स्वर्ण के अलावा, भारत ने तीन रजत पदक अर्जित

किए - हरविंदर और विवेक चिकारा (रिकर्व पुरुष युगल), राकेश कुमार और श्याम सुंदर स्वामी (कंपाउंड पुरुष युगल), और राकेश कुमार और ज्योति (कंपाउंड मिश्रित टीम) - और तीन कांस्य, रिकर्व महिला युगल (पूजा और भावना), डब्ल्यू1 पुरुष युगल (नवीन दलाल और नूरुद्दीन), और कंपाउंड महिला ओपन (ज्योति)।

(iii) चीन ने आठ टीम स्पर्धाओं में से छह स्वर्ण पदक जीतकर अपना दबदबा दिखाया, हालाँकि भारत की दो टीम जीत ने उसके दूसरे स्थान को काफ़ी मज़बूत किया। उल्लेखनीय चीनी तीरंदाज़ झांग तियानक्सिन ने W1 और मिश्रित स्पर्धाओं में तीन स्वर्ण पदक जीते।

IMPORTANT DAYS

1. जैव-आधारित नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए 7 जुलाई को विश्व स्तर पर विश्व जैव-उत्पाद दिवस 2025 मनाया गया।

7 जुलाई 2025 को विश्व जैव-उत्पाद दिवस (World Bioproduct Day) वैश्विक स्तर पर मनाया गया ताकि पर्यावरणीय स्थिरता और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करने में जैव-उत्पादों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। यह वार्षिक दिवस हर साल जैव-आधारित नवाचारों को प्रोत्साहित करता है जो हरित अर्थव्यवस्था और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देते हैं।

• इस दिन की शुरुआत वर्ष 2021 में वर्ल्ड बायोइकोनॉमी फोरम (WBEF) और वर्ल्ड बायोइकोनॉमी एसोसिएशन (WBA) द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पौधों, जलस्रोतों, कचरे और प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त जैविक विकल्पों को बढ़ावा देना जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन आधारित उत्पादों का विकल्प बन सकते हैं।

• जैव-उत्पादों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है – पारंपरिक और नवाचारी जैव-उत्पाद। पारंपरिक जैव-उत्पादों में लकड़ी, कागज और प्राकृतिक रेशे जैसे तत्व आते हैं जो सतत उद्योगों का आधार हैं। वहीं, नवीन जैव-उत्पादों में बायोप्लास्टिक, खाद्य अपशिष्ट से बने बायो-केमिकल्स, और नायलॉन से बने बायो-टेक्सटाइल्स जैसे नवाचार शामिल हैं।

• ये नवाचार प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने और अपशिष्ट को मूल्यवर्धित उत्पादों में बदलने में मदद करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) विशेषकर SDG 12 (उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन) और SDG 13 (जलवायु कार्रवाई) के अनुरूप हैं।

Key Points:-

(i) विश्व जैव-उत्पाद दिवस 2025 के अवसर पर भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MoS&T) के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने "The BioE3 Way 2025" अभियान के माध्यम से देशव्यापी जागरूकता कार्यक्रम में भाग लिया। इस अभियान में पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और रोजगार के तीन स्तंभों को मुख्य रूप से प्रस्तुत किया गया।

(ii) कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2030 तक 300 बिलियन अमरीकी डॉलर की जैव-आर्थिकी (Bioeconomy) विकसित करने की भारत सरकार की योजना की घोषणा की। यह रणनीति BioE3

(Biotechnology for Economy, Environment, and Employment) नीति के अंतर्गत लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य नवाचार, स्टार्टअप्स और सतत उत्पाद विकास को बढ़ावा देना है।

(iii) भारत की भागीदारी में "Voices Across the Cities" नामक राष्ट्रीय संवाद श्रृंखला भी शामिल थी, जिसमें समुद्री जैविक उत्पादों, कृषि अपशिष्ट, और जैव-ईंधन पर आधारित चर्चाएं की गईं। भारत की बायोटेक स्टार्टअप पारिस्थितिकी प्रणाली 10 वर्षों में 50 से बढ़कर 11,000 स्टार्टअप तक पहुंच गई है और इसे अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 जैसे कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है।

DEFENCE

1. भारत ने INS कवरत्ती से ERASR पनडुब्बी रोधी रॉकेट का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया।

भारत ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जब रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने INS कवरत्ती पर विस्तारित रेंज एंटी-सबमरीन रॉकेट (ERASR) के सफल उपयोगकर्ता परीक्षणों को संपन्न किया, जिसे 23 जून से 7 जुलाई, 2025 के बीच अंजाम दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई सराहना के अनुसार, ये परीक्षण भारत की बढ़ती रणनीतिक पनडुब्बी युद्ध क्षमताओं की पुष्टि करते हैं।

• ERASR मौजूदा RGB-60 रॉकेट का स्वदेशी अपग्रेड है, जिसे DRDO प्रयोगशालाओं - आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट (ARDE), हाई एनर्जी मैटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी (HEMRL) और नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी (NSTL) द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है - जिसमें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (हैदराबाद) और सोलर डिफेंस एंड एयरोस्पेस लिमिटेड (नागपुर) की विनिर्माण साझेदारी शामिल है।

Key Points:-

(i) सत्रह ERASR रॉकेटों का परीक्षण लघु एवं दीर्घ दूरी के प्रोफाइलों पर ~8.9 किमी तक किया गया, जिसमें ट्विन-मोटर विन्यास, स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक टाइम-फ्यूज और सटीक वारहेड प्रदर्शन शामिल थे, जो परिचालन तत्परता और स्वदेशी रॉकेट लांचर (IRL) प्रणाली के साथ एकीकरण को प्रदर्शित करता है।

(ii) परीक्षणों ने विभिन्न गहराइयों और दूरियों पर पानी के भीतर मौजूद खतरों से सटीक रूप से निपटने की ERASR की क्षमता की पुष्टि की, जिससे नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्धक क्षमता में वृद्धि हुई। यह प्रणाली रूसी मूल की RGB प्रणालियों की जगह लेगी और भारतीय नौसैनिक जहाजों की मारक क्षमता को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाएगी।

(iii) रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और नौसेना को बधाई देते हुए कहा, "इस प्रणाली के सफलतापूर्वक शामिल होने से भारत की समुद्री मारक क्षमता में वृद्धि होगी," और आत्मनिर्भर भारत के तहत आत्मनिर्भरता और उन्नत संप्रभु रक्षा तकनीक के लिए देश के मार्ग को रेखांकित किया। अब इस रॉकेट के नौसेना सेवा में शामिल होने की उम्मीद है, जो भारत की ASW तैयारियों में एक बड़ा कदम होगा।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. भारत स्पेस TS और सिनर्जी क्वांटम के बीच साझेदारी में पहला स्वदेशी क्वांटम-सिक्योर उपग्रह विकसित करेगा।

भारत ने अंतरिक्ष साइबर सुरक्षा में एक बड़ी छलांग लगाई है, जिसके तहत बेंगलुरु स्थित स्पेस TS ने जुलाई 2025 में स्विट्जरलैंड के सिनर्जी क्वांटम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य देश का पहला स्वदेशी क्वांटम-सुरक्षित उपग्रह विकसित करना है, जो पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और AI-एकीकृत उपग्रह प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाकर सुरक्षित, एन्क्रिप्टेड संचार सुनिश्चित करेगा।

• उपग्रह में पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी (PQC) एम्बेडेड होगी, जो भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों द्वारा उत्पन्न खतरों से डेटा ट्रांसमिशन की सुरक्षा करेगी। RSA और ECC जैसी पारंपरिक एन्क्रिप्शन विधियों के विपरीत, PQC क्वांटम-प्रतिरोधी प्रोटोकॉल, कठोर फ़र्मवेयर और सुरक्षित क्रिप्टो-चिप्स के माध्यम से दीर्घकालिक गोपनीयता सुनिश्चित करता है—जिससे उपग्रह क्वांटम-युग के साइबर खतरों के प्रति लचीला बनता है।

• स्पेस TS मुख्य उपग्रह इंजीनियरिंग का काम संभालेगा, जिसमें पेलोड एकीकरण और कक्षीय मिशन योजना शामिल है, जबकि सिनर्जी क्वांटम पोस्ट-क्वांटम सॉफ़्टवेयर आर्किटेक्चर और एन्क्रिप्शन परतों में योगदान देगा। इस सहयोग का उद्देश्य संपूर्ण क्वांटम-सुरक्षित संचार का निर्माण करना है, जो AI-सहायता प्राप्त नियंत्रण तंत्रों और सुरक्षित कुंजी विनिमय का उपयोग करके ग्राउंड स्टेशनों, उपग्रह समूहों और ड्रोनों को जोड़ेगा।

• यह स्वदेशी उपग्रह पहल भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष अवसंरचना में तकनीकी आत्मनिर्भरता हासिल करना है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा प्रणालियों, महत्वपूर्ण अवसंरचना लचीलेपन और डिजिटल संप्रभुता का समर्थन करता है, जिससे भारत क्वांटम अंतरिक्ष पहलों में यूरोपीय संघ और चीन जैसे अग्रणी देशों के साथ खड़ा हो जाता है।

Key Points:-

(i) यह उपग्रह क्वांटम कुंजी वितरण (QKD) के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में भी काम करेगा, जो एन्क्रिप्शन कुंजी साझाकरण का एक अत्यधिक सुरक्षित रूप है। इसकी अतिरिक्त कार्यक्षमताओं में एन्क्रिप्टेड टेलीमेट्री सिस्टम, AI-संचालित तारामंडलों पर स्वायत्त नियंत्रण, और राष्ट्रीय एवं वाणिज्यिक रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त सुरक्षित भंडारण एवं संचार ढाँचे शामिल होंगे।

(ii) एक बार चालू हो जाने पर, इस उपग्रह का उपयोग सुरक्षित स्वार्म ड्रोन संचालन, बहु-कक्षा एन्क्रिप्टेड नेटवर्क और अंतरिक्ष-आधारित क्लाउड कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकों के लिए भी किया जा सकेगा। इससे भारत को नागरिक और रक्षा क्वांटम अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण बढ़त मिल सकती है, जिससे वैश्विक स्तर पर तेज़ी से बढ़ते क्वांटम संचार पारिस्थितिकी तंत्र में उसकी उपस्थिति मज़बूत हो सकती है।

2. HCLSoftware ने सरकारी और विनियमित डेटा की सुरक्षा के लिए सॉवरेन AI 'डोमिनो IQ' के साथ डोमिनो 14.5 लॉन्च किया।

एचसीएलटेक के एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर प्रभाग, एचसीएलसॉफ्टवेयर ने हाल ही में डोमिनो 14.5 जारी किया है, जिसमें डोमिनो आईक्यू शामिल है - एक शक्तिशाली संप्रभु एआई एक्सटेंशन जो सरकारों, वित्तीय संस्थानों और अन्य विनियमित क्षेत्रों के लिए लक्षित है, जिन्हें डेटा गोपनीयता और एआई उपयोग पर मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता होती है।

- **डोमिनो IQ संगठनों को इन-हाउस या सत्यापित भागीदारों द्वारा निर्मित विश्वसनीय एआई मॉडल का उपयोग करने में सक्षम बनाता है—जो एल्गोरिदम और डेटा पर विस्तृत नियंत्रण प्रदान करता है। यह यूरोपीय एआई अधिनियम जैसे सख्त ढाँचों का अनुपालन सुनिश्चित करता है और विदेशी क्लाउड प्रदाताओं पर निर्भरता को समाप्त करता है।**

- **HCLSoftware की रिपोर्ट है कि 200 से अधिक सरकारी एजेंसियां पहले से ही अपडेटेड प्लेटफॉर्म का उपयोग करके संवेदनशील सामग्री - ईमेल, चैट, वीडियो कॉल, दस्तावेज - की सुरक्षा कर रही हैं।**

Key Points:-

(i) सुरक्षा में नाटकीय रूप से सुधार किया गया है: डोमिनो 14.5 सूचना सुरक्षा के लिए BSI-प्रमाणित है, सुरक्षा घटना और घटना प्रबंधन (SEIM) उपकरणों को एकीकृत करता है, और समावेशी पहुँच के लिए यूरोपीय पहुँच अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करता है। इसमें अत्यधिक विनियमित और गोपनीय वातावरणों के लिए अनुकूलित, उपयोग के लिए तैयार सॉवरेन चैट और वीडियो-मीटिंग क्षमताएँ भी शामिल हैं।

(ii) HCLSoftware ने यूरोप के एक प्रमुख सॉवरेन क्लाउड प्रदाता, आईओएनओएस के साथ साझेदारी की है ताकि डोमिनो 14.5 को ऐसे बुनियादी ढाँचे में होस्ट किया जा सके जो डेटा रेजिडेंसी की गारंटी देता है और विदेशी पहुँच के जोखिमों को समाप्त करता है। IONOS के CEO अचिम वीस ने इस मॉडल को विनियमित उद्योगों में "डिजिटल आत्मनिर्णय" के एक मानक के रूप में रेखांकित किया।

(iii) HCLSoftware के कार्यकारी उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक रिचर्ड जेफ्ट्स के अनुसार, यह अपडेट बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य को संबोधित करता है, जहां सार्वजनिक और निजी नियामक - विशेष रूप से सरकारें और निजी बैंक - राष्ट्रीय और वाणिज्यिक डेटा अखंडता की रक्षा के लिए संप्रभु AI-आधारित सहयोग उपकरणों की मांग कर रहे हैं।

Static GK

National Institution for Transforming India (NITI Aayog)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम	मुख्यालय: नई दिल्ली
Punjab	राजधानी: चंडीगढ़	मुख्यमंत्री: भगवंत मान
Bihar	मुख्यमंत्री: नीतीश कुमार	राज्यपाल: आरिफ मोहम्मद खान
Apple Inc.	CEO : टिम कुक	मुख्यालय: क्यूपर्टिनो, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका
BMW Canada Inc.	अध्यक्ष एवं CEO : हरदीप सिंह बराड़	मुख्यालय: म्यूनिख, जर्मनी
DRDO	अध्यक्ष: समीर वी. कामत	मुख्यालय: नई दिल्ली
Andhra Pradesh	मुख्यमंत्री: एन. चंद्रबाबू नायडू	राज्यपाल: एस. अब्दुल नज़ीर
Brazil	राजधानी: ब्रासीलिया	राष्ट्रपति: लुइज़ इनासिओ लूला दा सिल्वा
World Archery	अध्यक्ष : चुंग	मुख्यालय :
Asia (WAA)	यूइसुन	सियोल, दक्षिण कोरिया